

# कृषि और संबद्ध क्षेत्र का याकल्प के लिए पारिश्रमिक दृष्टिकोण

इस लेख को अद्यतन करने की आवश्यकता है। हाल की घटनाओं या नई उपलब्ध जानकारी को प्रतिबिंबित करने के लिए कृपया इस लेख को अपडेट करें। (अक्टूबर 2015)

कृषि और संबद्ध क्षेत्र का याकल्प के लिए पारिश्रमिक दृष्टिकोण  
देश भारत

प्रधानमंत्री (मन) मनमोहन सिंह

अगस्त 2007 को लॉन्च किया गया

बंद रहता है 2012

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बहाल

नाम दिया गया - कृषि और संबद्ध क्षेत्र का याकल्प के लिए पारिश्रमिक दृष्टिकोण

स्थिति बंद रहता है

वेबसाइट <http://rkvy.nic.in>

कृषि और संबद्ध क्षेत्र का याकल्प (RAFTAAR) के लिए पारिश्रमिक दृष्टिकोण, पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हिंदी: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, लिट। 'राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम' [1]) अतिरिक्त केंद्रीय सहायता [2] की एक राज्य योजना योजना है। भारत सरकार द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अगस्त 2007 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के तत्वावधान में शुरू की गई, यह 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007) की अवधि के दौरान कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों (योजना आयोग (भारत) द्वारा परिभाषित) के विकास के माध्यम से कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल करना चाहता है। -11)। [3]

## अंतर्वस्तु

1 लक्ष्य

2 पात्रता

3 अनुदान

4 प्रदर्शन

5 परिवर्धन

6 यहभीदेखें

7 सन्दर्भ

8 बाहरीलिंक

## लक्ष्य

यहकार्यक्रमअनिवार्यरूपसेएकराज्ययोजनायोजनाहैजोराज्योंऔरभारतकेराज्योंकोस्थानीयआवश्यकताओं, भौगोलिक / जलवायुपरिस्थितियों, उपलब्धप्राकृतिकसंसाधनों / प्रौद्योगिकीऔरफसलपरजानकारीकोशामिलकरकेकृषिमेंसार्वजनिकनिवेशबढ़ानेकीस्वायत्तताप्रदानकरनेकीकोशिशकरताहै। कृषिऔरइसकेसंबद्धक्षेत्रोंकीउत्पादकताकोबढ़ानेकेलिएऔरअंततःकृषिऔरसंबद्धक्षेत्रोंमेंकिसानोंकीवापसीकोअधिकतमकरनेकेलिएउनकेजिलोंमेंपैटर्न। [४] [५]

## पात्रता

एकराज्य RKVY

केतहतवित्तपोषणकेलिएपात्रहैयदिवहकृषिऔरउसकेसंबद्धक्षेत्रोंपरकुलराज्ययोजनाव्ययकेसंबंधमेंअपनेव्ययकाप्रतिशतबनाएरखताहैयाबढ़ाताहै, जहांइसखर्चकेलिएबेसलाइन

(जोहरसालस्थानांतरितहोगी)

हैराज्यसरकारद्वारापिछलेतीनवर्षोंसेकृषिऔरउसकेसंबद्धक्षेत्रोंपरकिएगएव्ययकेप्रतिशतकाऔसतकृषिऔरउससेसंबद्धक्षेत्रोंसेसंबंधितकोईभीनिधिहैजोइसेउससमयमेंअपनीराज्ययोजनाकेतहतप्राप्तहोसकतीहै।

निम्नलिखितकाल्पनिकस्थितिपरविचारकरेंजहांराज्य 2010-11

केलिएआरकेवीवाईकेतहतपात्रताचाहताहै।कृषिऔरसंबद्धक्षेत्रोंपरवर्षव्यय

(आरकेवीवाईकेतहतप्राप्तमाइनसफंड) (रु।करोड़में) राज्ययोजनाकेतहतकुलपरिव्यय (रु।करोड़में) प्रतिशत।

2007-08	200	2000	10%
2008-09	150	2000	7.5%
2009-10	175	2250	7.7%
2010-11	198	2200	9%

वर्ष 2010-11 केलिएआरकेवीवाईकेतहतवित्तपोषणकेलिएपात्रहोनेकेलिए, राज्यकेपासवर्ष 2007-08,08-09 और 09-10

केऔसतसेअधिकव्ययकाप्रतिशतहोनाचाहिए।  $\{10\% + 7.5\% + 7.7\%\} \{3\}$  8.4  $\% = \frac{10\% + 7.5\% + 7.7\%}{3}$ ।चूंकि 2010-11

मेंव्ययकाप्रतिशतआधारभूतप्रतिशत 0.6% सेअधिकहै,

इसलिएराज्यआरकेवीवाईकेतहतधनकेआवंटनकेलिएपात्रहै।यदिबादकेवर्षोंमेंव्ययआधाररेखासेनीचेआताहै,

तोआरकेवीवाईकेतहतशुरूकीगईपरियोजनाओंकोपूराकरनेकेलिएआवश्यकसंसाधनअब राज्यसरकारद्वाराप्रदानकिएजाएंगे। [५]

*अनुदान*

यह निर्णय लिया गया कि that 58.75 बिलियन (यूएस \$ 850 मिलियन)

केंद्र सरकार द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हर साल जारी किया जाएगा और 2007-08 में (15 बिलियन (यूएस \$ 220 मिलियन) आवंटित किया जाएगा। [6]

आरकेवीवाई के कार्यान्वयन के पहले तीन वर्षों (2007-2010) के दौरान, US 84,621 मिलियन (यूएस \$ 1.2 बिलियन) की राशि, जो लगभग 250 बिलियन (आर \$ 3.6 बिलियन) के आरकेवीवाई के तहत कुल आवंटन का 33% है। [7]

भारत के केंद्रीय बजट को पेश करते हुए, भारत के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि 2010-11 में RKVY के तहत आवंटन मौजूदा .5 67.55 बिलियन (US \$ 980 मिलियन) से बढ़कर billion 78.6 बिलियन (US \$ 1.1 बिलियन) होगा था। 2011-12। [8] 2016-17 के दौरान रिलीज की स्थिति 24 अगस्त 2016 को राज्य राशिकानाम (करोड़ रुपये में) और रिलीज की तारीख के आंकड़े आंध्र प्रदेश रु .11.89 (19.08.2016) छत्तीसगढ़ Rs.90.06 (2016/05/23) जम्मू और कश्मीर Rs.16.16 (19.08.2016) कर्नाटक Rs.202.93 (2016/07/28) मध्य प्रदेश Rs.155.13 (23.05.2016) महाराष्ट्र Rs.200.24 (2016/05/24) मणिपुर Rs.11.86 (2016/07/15) नागालैंड Rs.14.86 (2016/08/19) ओडिशा Rs.45.86 (2016/05/23) राजस्थान Rs.198.71 (2016/07/14) तमिलनाडु Rs.152.87 (24.05.2016)